

"मुझे अखबार निकालने दो तो मैं इस बात की परवाह नहीं करता कि कौन धर्म का नियामक है और कौन कानून का निर्माता"—वेडेल फिलिप्पा

दैनिक भारतीय बस्ती

बस्ती 20 अप्रैल 2025 रविवार

सम्पादकीय

विदेशों में पढाई से होता मोह भंग

यह खबर चौंकारने वाली है कि बीते साल विदेश जाने वाले छात्रों की संख्या में 25 फीसदी की कमी आई है। जबकि अमेरिका जाने वाले छात्रों की संख्या में 36 और कनाडा जाने वाले छात्रों की संख्या में 34 फीसदी की कमी आई है। कमोबेश यही स्थिति ब्रिटेन की भी है। ये आंकड़े वर्ष 2024 के हैं। निश्चित तौर पर जब ट्रंप काल में उछाड़-पछाड़ के दौर के आंकड़े सामने आएंगे, तो वे ज्यादा चौंकारने वाले होंगे। एक समय था कि छात्रों में परदेस जाकर पढाई करने का जुनून उफान पर था। हर साल मां-बाप खून-पसीने की कमाई से और अपना पेट काटकर बच्चों को पढ़ने के लिये विदेश भेज रहे थे। कहीं-कहीं तो खेत बेचकर और घर गिरवी रखकर बच्चों को विदेश पढ़ाने के लिए भेजने के मामले भी प्रकाश में आए। दरअसल, देश में बैंकों से एजुकेशन लोन मिलने की सुविधा ने भी छात्रों की विदेश यात्रा को सुगम बनाया। हर साल लाखों छात्र सुनहरें सपने लिये विदेश गमन कर रहे थे। ये जुनून पंजाब में विशेष रूप से देखा गया, जो कनाडा-अमेरिका आदि देशों में संपूर्ण भारत से जाने वाले छात्रों का साठ फीसदी था। जरूरी नहीं था कि ये सारे छात्र मेधावी थे और सब दुनिया के शीर्ष विश्वविद्यालयों में दाखिला पा रहे थे। इनमें कई विश्वविद्यालय ऐसे भी थे जो सिर्फ विदेशी छात्रों से कमाई करने के मकसद से चलाए जा रहे थे। वहीं कुछ विश्वविद्यालय ऐसे भी थे जो अवैध रूप से लोगों को विदेश भेजने वाले एजेंटों की कमाई का जरिया बने हुए थे। युवाओं को छात्र के रूप में इन देशों में भेजकर मोटी रकम वसूली जा रही थी। दरअसल, धीरे-धीरे छात्रों और उनके अभिभावकों को हकीकत का अहसास होता चला गया। उन्होंने महसूस किया कि वे मोटा पैसा खर्च करके जैसे-तैसे डिग्री तो पा सकते हैं, लेकिन ये नौकरी व ग्रीन कार्ड की गारंटी नहीं है। हां, कुछ छात्र किसी तरह छोटे-मोटे काम-धंधे करके अपनी पढाई का खर्चा व घर का कर्जा उतारने का गुमाड जरूर कर लेते थे।

दरअसल, धीरे-धीरे अमेरिका, ब्रिटेन व कनाडा सरकारों के दुराग्रहों व उनकी प्राथमिकताओं ने छात्रों को खुरदुरी जमीन के यथार्थ से रूबरू करा दिया। छात्रों को एजेंटों ने जो सबजबाब दिखाए थे, उनकी हकीकत सामने आने लगी। इसके अलावा कोरोना काल के बाद बिखरती अर्थव्यवस्थाएं, नौकरी के आकर्षक प्रस्तावों में कमी, वीजा मिलने में हो रही दिक्कतें, इन देशों के गौरी समझी वाले लोगों के भारतीयों पर बड़े हमलों ने छात्रों में मोहभंग की स्थिति उत्पन्न कर दी। बीते साल अमेरिका में कई भारतीय छात्रों पर नस्लीय हमले हुए। कई छात्रों की हत्या हुई और अनेक घायल हुए। कनाडा व ब्रिटेन में भारत विरोधी अभियानों तथा कनाडा में जस्टिस ट्रूडो के भारत विरोधी रवये ने भी छात्रों का मोहभंग किया। वैसे देखा जाए तो विदेशी मुद्रा अर्जित करने के बजाय हम हर साल अरबों रुपये इन देशों को भेज रहे थे। दूसरी ओर छात्रों के विदेश जाने के मोहभंग होने का सार्थक पहलू यह भी है कि अब ये प्रतिभाएं देश में रहकर राष्ट्र के विकास में योगदान दे सकती हैं। कुदरत का नियम है कि अपनी उर्वरा भूमि में ही पौधे अनुकूल वातावरण के चलते खिलते-निखरते हैं। ये हमारे नीति-नियंताओं की विफलता है कि आजादी के सत्त दशक बाद भी हम देश को अंतर्राष्ट्रीय मामकों वाले विश्वविद्यालय नहीं दे पाये। सामान्य शिक्षा में कौशल विकास के गुण को विकसित नहीं कर पाए। छात्रों में सरकारी नौकरियां पाने की लासला की रचनात्मक विकल्प नहीं दे पाये। अमेरिका की सिलिकॉन वैली से लेकर आस्ट्री में सबसे ज्यादा युवाओं वाला देश है। यदि हम उनकी क्षमता,योग्यता और प्रतिभा का बेहतर उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, तो यह हमारी बड़ी नाकामी है। देश के सत्ताधीशों को इस दिशा में गंभीरता से सोचना होगा कि क्यों छात्रों में विदेश जाने की हाल लगी रहती थी। छात्रों को अनुकूल वातावरण देकर ही विकसित भारत के संकल्प पूरे हो सकते हैं।



— ललित गर्ग —

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज पर संसद की स्थायी समिति ने महत्वा गंभी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून (मनरेगा) के तहत प्रदान किए जाने वाले काम के दिनों की संख्या 100 से बढ़ाकर 150 दिन करने समेत श्रमिकों के दैनिक पारिश्रमिक को कम से कम 400 रुपए निर्धारित करने की सिफारिश की है, इन सिफारिशों से न केवल यह योजना अधिक सशक्त एवं प्रभावी होकर ग्रामीण जनजीवन के कमजोर लोगों के लिये राहत का माध्यम बनेगी, बल्कि ग्रामीण जीवन को नये भारत की बुनियाद बानेगी। मनरेगा भारत सरकार द्वारा ग्रामीण गरीब एवं कमजोर लोगों के लिए उठाया गया एक क्रांतिकारी कदम है और वर्तमान में यह भारत में सबसे बड़ा रू-लक्ष्यीकरण कार्यक्रम है। यह सामाजिक सुरक्षा, आजीविका सुरक्षा और लोकातांत्रिक सशक्तिकरण के माध्यम से ग्रामीण भारत में समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए एक प्रभावशाली साधन है। जो नये भारत, सशक्त भारत, विकसित भारत का आधार होगा।

मनरेगा में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक अकेछण और शिकायत निवारण तंत्र की व्यवस्था है, बावजूद मनरेगा में भी भ्रष्टाचार, अफसरशाही, अनियमितता, कोटाही के कारण इस महत्व योजना पर भी समय-समय का आधार होगा।



अंधेरा छाता रहा है। यों तो गिरवट हर स्तर पर है। समस्पाए भी अनेक मुखरित हैं पर राष्ट्रीय चरित्र को विघटित करने वाले भ्रष्टाचार एवं अनियमितता की काली छाया मनरेगा पर न पड़े, इसलिये स्थायी समिति का यह सुझाव स्वागतयोग्य है कि श्रमिकों की संसुष्टि, वतन में देशी, मातृभाषी के रूझान और योजना में वित्तीय अनियमितताओं पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। इसीलिये समिति ने मनरेगा से जुड़े कार्यक्रम की कमियों के बारे में अहम जानकारी प्राप्त करने और मनरेगा की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए आवश्यक नीतिगत सुधारों को लागू करने के लिए देशभर में स्वतंत्र एवं पारदर्शी संरक्षण की सिफारिश की है। समिति ने उभरती चुनौतियों के मद्देनजर योजना को नया रूप देने पर भी जोर दिया है। मनरेगा बदलते षक और उभरती चुनौतियों के बावजूद मात्र भी प्राणिक है।

मनरेगा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर नैदा करता है, जिससे लोगों को आय प्राप्त होती है और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होता है, यह योजना टिकाऊ प्रतियां जैसे सड़क, नहर, तालाब, कुएं बनाने

पर जोर देती है, जो ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास में योगदान करती है। भारत आज भी गांवों का देश है, विकास की गंगा गांवों से होकर ही निकलती है। मनरेगा ग्रामीण परिवारों की आजीविका सुरक्षा को बढ़ाता है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां अन्य रोजगार के अवसर सीमित हैं, यह श्रम शक्ति के सशक्तिकरण का प्रभावी माध्यम है। यह योजना ग्रामीण महिलाओं को रोजगार प्रदान करती है, जिससे वे सशक्त हो पाती हैं और समाज में सक्रिय भूमिका निभा पाती हैं। यदि किसी व्यक्ति को मनरेगा के तहत 15 दिनों के भीतर काम नहीं मिलता है, तो उन्हें बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है, जो एक सुरक्षा जाल के रूप में कार्य करता है। मनरेगा एक बहुआयामी योजना है, जिसके तहत विभिन्न उत्पादक परिप्रेक्षियों का निर्माण किया जाता है, जैसे कि जल संरक्षण संरचनाएं, ग्रामीण सड़कें, और अन्य बुनियादी ढांचे की परियोजनाएं, जो ग्रामीण अव्यवस्था को बढ़ावा देती हैं। मनरेगा के तहत रोजगार एक कानूनी अधिकार है, जिसका अर्थ है कि प्रत्येक पार व्यक्ति को रोजगार का दावा करने का अधिकार है। इस दूरगामी

एवं ग्रामीण जनजीवन के उन्नयन एवं उत्थान के कार्यक्रम के लागू होने के बाद लाखों मजदूरों को काम मिला है। पलायन में काफ़ी हद तक कमी आई। मनरेगा ने साबित किया कि भारत में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए वह आज भी उम्मीद की किरण है। इस कार्यक्रम से लाखों अकुशल श्रमिकों और महिलाओं को पूरे वर्ष में सौ दिन के रोजगार की गारंटी मिली। इससे बड़ी संख्या में ग्रामीण परिवार लाभान्वित हुए। यह वजह है कि इस कार्यक्रम में काम के दिन बढ़ाने की मांग अवसर उठती रही है। एक संकीर्ण स्तर पर काम के दिनों की संख्या बढ़ा कर पांच महीने यानी 150 सौ दिन करने और दैनिक पारिश्रमिक कम से कम चार सौ रुपए करने की सिफारिश की है, जो प्रासंगिक एवं बढ़ती महंगाई को देखते हुए जरूरी है। दरअसल, अभी इस कार्यक्रम के तहत मिलने वाली मजदूरी न्यूनतम जरूरतें एवं बुनियादी दैनिक खर्चों को पूरा करने के लिए भी अपर्याप्त है। मजदूरी वर्तमान आर्थिक वास्तविकताओं के अनुरूप हों और ग्रामीण श्रमिकों को

समानजनक पारिश्रमिक प्रदान करें। रोजगार योजना के लिए आर्बिट्रट राशि में लंबे समय से ठहराव को समिति की जिता इसी संदर्भ में है। कोई दो राय नहीं कि इसकी राशि बढ़ने से इसकी प्रभावशीलता बढ़ेगी। समिति ने कहा, बदलते समय और उभरती चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए योजना में सुधार की आवश्यकता है। समिति मंत्रालय से उन विकल्पों पर विचार करने का आग्रह करती है, जिससे मनरेगा अधिक सशक्त, पारदर्शी एवं प्रभावी बन सके। यह प्रणामनीय नरेंद्र मोदी के ग्रामीण विकास योजना को बल देने में सहायक है। हालांकि मनरेगा निरन्तर सवालों से घिरी रही है, इसमें वित्तीय अनियमितता की भी शिकायतें मिलती रही हैं। इसके प्रति श्रमिकों का रुझान बढ़ते और मजदूरी दर से मिलने पर सवाल उठते रहें हैं। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय की स्थायी समिति ने तीन साल पहले मनरेगा का विश्लेषण करते हुए कई सुझाव दिए थे। तब उस समिति ने भी इस कार्यक्रम को नया रूप देने के लिए काम के गारंटीशुदा दिनों को सौ से बढ़ा कर डेढ़ सौ करने की सिफारिश की थी और सभी राज्यों में समान मजदूरी दर करने का सुझाव दिया था। अब संसद की समिति ने उन सुझावों पर एक तरह से मुहर लगाई है। अगर मनरेगा में नीतिगत सुधारों को लागू करने के लिए स्वतंत्र और पारदर्शी संरक्षण होगा, तो इसके बेहतर परिणाम सामने आएंगे।

मनरेगा ने अपनी ताकिक सामर्थता साबित की है, लेकिन अभी इसमें व्यापक सुधारों की अपेक्षा है। देखने में आता है मनरेगा से लाभान्वित लोगों को अवसर निना काम के ही राशि दी जा रही है, सरकार को इन लोगों की श्रम-शक्ति को देश-विकास के कठोर ने नियोजित करने पर भी ध्यान देना चाहिए। मनरेगा योजना के अन्तर्गत कौशल विकास पर बल दिया जाना चाहिए।

योजना भले ही अकुशल श्रमिकों के लिए अवसर प्रदान करने पर केंद्रित है, लेकिन उन्हें अपने कौशल को विकसित करने और बढ़ाने का अवसर मिलने से यह योजना देश-विकास का माध्यम बन सकती है। वनीकरण, जल संरक्षण और सड़क निर्माण जैसी विभिन्न परियोजनाओं में उनकी भागीदारी से श्रमिकों को व्यावहारिक अनुभव प्राप्त होगा। वे नए कौशल सीख सकते हैं जिनका उपयोग मनरेगा द्वारा प्रदान किए जाने वाले भविष्य के रोजगार अवसरों के लिए किया जाएगा। मनरेगा योजना सड़कों, नहरों, तालाबों और सिंचाई सुविधाओं जैसे परिसरियों के विकास का समर्थन करते हुए रोजगार प्रदान करे, इस योजना को कनेक्टिविटी, कृषि उत्पादकता, जन-विकास से भी जोड़ा जाना चाहिए ताकि प्रकृति के ससाधनों को बचावे, पारिस्थितिक संतुलन को बहाल करने और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने में मदद मिल सके। जिससे ग्रामीण जीवन में नए मनुष्य का जन्म होगा। नई पात्रता का निर्माण होगा, जहां हमारी ग्रामीण संस्कृति पुनः अपने मूल्यों, विरासत एवं उपयोगिता के साथ प्रतिष्ठापित होगी। मनरेगा योजना अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) सहित समाज के हाशिए पर पड़े समूहों को समाप्त रूप से प्रदान करने पर केंद्रित है। यह सुनिश्चित करता है कि इन कमजोर समूहों को रोजगार कर समाप्त रूप से मिले और उनके साथ विश्व की तरह का सम्बन्ध न हो। ताकि एक संतुलित, समाप्ततामूलक एवं आदर्श समाज-व्यवस्था को आकार दिया जा सके। मनरेगा योजना ग्रामीण विकास, गरीबी उन्मुख, कौशल संकट और परिवर्तनशील स्थिरता में महत्वपूर्ण आधार बनकर सामने आये। तभी ग्रामीण परिवारों को सशक्त बनाने और भारत में ग्रामीणों के व्यापक विकास को अवसरित करने का सूरज चमक सकेगा।

पाकिस्तान के नफरत की मानसिकता

—अजय कुमार—



1947 में पाकिस्तान की बुनियाद हिन्दुओं से नफरत करने के कारण पड़ी थी। आज करीब 77 वर्षों के बाद भी पाकिस्तान हिन्दुओं के प्रति ऐसा ही रवैया लेकर आगे बढ़ रहा है। आज भी यह हिलसिला जारी है। इसी परिपाटी को आगे बढ़ाते हुए पाक की फौजी हुकुमत एक बार फिर पुराना राग अलावा रही है। इस्लामाबाद में हाल ही में हुए प्रवासी पाकिस्तानियों के सम्मेलन में पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असिम मुनीर ने कश्मीर के मुद्दे पर उल्लेख करते बयान दिए, जिसने न केवल वैश्व शांति को नुकसान हुआ है, बल्कि यह भी साबित हो गया कि पाकिस्तान की सत्ता संरचना अब भी नफरत और विघटन की राजनीति को अपनी ताकत मानी है। मौजूदा जनरल मुनीर का हाल ही में दिया गया बयान, जिसमें उन्होंने कश्मीर को पाकिस्तान की शग्ले की नसब बताया, ने एक बार फिर साबित कर दिया कि पाकिस्तान की सोच में कोई बदलाव नहीं आया है। यही सच पिछले कई दशकों से पाकिस्तान की फौजी हुकुमत द्वारा लगातार दोहराया जाता रहा है। पाकिस्तान के जनरल यह हमेशा कहते रहते हैं कि कश्मीर पाकिस्तान के लिए अखंड महत्वपूर्ण है, और इसे कभी भी जापान से अलग नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन क्या इस विश्वास में पाकिस्तान को किसी प्रकार का लाभ पहुंचाया है? पाकिस्तान की अव्यवस्था जर्जर हो चुकी है, आर्थिकव्यवस्था की पोक छिन्न बन चुकी है और वैश्विक मंच पर वह अलग-थलग पड़ा हुआ है।

पाकिस्तान की वर्तमान स्थिति किसी से छिपी नहीं है। इन्हीं हसरतों के कारण वह आर्थिक रूप से कमजोर होता जा रहा है। आईएमएफ की रिपोर्ट के अनुसार 2025 के शुक्राब्दी मूल्यांकन में पाकिस्तान का विश्वी मुद्रा संकट मध्य 3.1 अरब डॉलर था, जो मुश्किल से कुछ हफ्तों का आयुध खर्च चला सकता है। महंगाई दर 30 प्रतिशत के पार जा चुकी है, बेरोजगारी करीब नौ प्रतिशत तक

पहुंच चुकी है और जनता राजनीतिक और आर्थिक अस्थिरता से त्रस्त है। ऐसे में पाकिस्तान की फौजी हुकुमत का इस प्रकार का उल्लास भरा बयान यह दर्शाता है कि पाकिस्तान के पास अब कोई दूसरा उपाय नहीं बाक है, विश्वास इसके कि वह अपने लोगों को बयान मटवाने के लिए पुराने और साम्प्रदायिक मुद्दों को उछाले।

बलूचिस्तान में अलगवादी राह की लम्पटें तेज होनी जा रही हैं, और यहां के लोग पाकिस्तानी सेना और सरकार के खिलाफ खुलेआम विद्रोह कर रहे हैं। बलूच विद्रोहियों ने हाल ही में पाकिस्तानी सेना के कई ठिकानों पर हमले किए हैं, जिससे पाकिस्तान के भीतर की अस्थिरता को और भी बढ़ावा मिला है। जनरल मुनीर का यह कहना कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का अभिमान है और कोई इसे नहीं छोड़ सकता, इस बात का स्पष्ट संकेत है कि उन्हें बलूचिस्तान की स्थिति को लेकर गंभीर जिता है। पाकिस्तान के भीतर के लोग यह सवाल कर रहे हैं कि आखिर कब तक कश्मीर के नाम पर उन्हें गुमराह किया जाएगा, जब उनके घरों में रोटीयां पकने की स्थिति नहीं है? यह सवाल पाकिस्तान की युवा पीढ़ी में और सोशल मीडिया पर महाराई से उठ रहा है, जहां रूस की आलोचना आम बात हो गई है। कई लोग खुलकर कह रहे हैं कि भारत के साथ फिर से मिल जाना ही बेहतर होगा, जो एक संकेत है कि पाकिस्तान में अब लोग अपनी अवल समस्याओं के बारे में गंभीर हो गए हैं।

जनरल मुनीर ने अपने भाषण में विश्वों में से पाकिस्तानियों से अपील की कि वे अपने बच्चों को यह सिखाएं कि पाकिस्तान क्यों बना और हिंदू और मुसलमान क्यों एक जैसे नहीं हो सकते। उनका यह बयान

खतरे में खाद्य और जल सुरक्षा



—ज्ञानेन्द्र रावत—



रेशियरों का तेजी से पिघलना वैश्विक जलवायु संकट का गंभीर संकेत है। यूनेस्को की विश्व जल विकास रिपोर्ट 2025 के अनुसार, यदि यह प्रक्रिया यू ही जारी रही तो इसके परिणाम विनाशकारी होंगे। इससे दो अरब से अधिक लोगों को पानी और भोजन की भारी किल्लत श्रेणी में संकट की है। रेशियर पृथ्वी के जल षक को संतुलित रखने में अहम भूमिका निभाते हैं, और इनके पिघलने से नदियों का अस्तित्व संकट में पड़ रहा है।

जलवायु परिवर्तन के कारण रेशियरों का तेजी से पिघलना और पंतीय क्षेत्रों में घटती वर्षाबारी पूरी दुनिया की खाद्य और जल सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन चुकी है। दुनिया में मौजूद 2.75 लाख से अधिक रेशियरों का सात लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र जलवायु परिवर्तन की मार झेल रहा है। संयुक्त राष्ट्र और विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अनुसार, सभी 19 रेशियर क्षेत्रों में लगातार तीन वर्ष से नुकसान देखा गया है, जिनमें नार्वे, स्वीडन और स्पारबोर्ग जैसे क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित हैं। कोलारगो नदी का सूखना इस संकट की मयवाहक को दर्शाता है। यूनेस्को के अनुसार, दुनिया के 70 फीसदी पेयजल का स्रोत रेशियर ही है, और इनके पिघलने से जल संकट और भी विकराल हो सकता है।

नासा और नेशनल स्नो एंड आइस डेटा सेंटर के शोध के अनुसार वर्ष 2010 से अब तक अर्कटिक और अंटार्कटिका की बर्फ में लाखों वर्ग किलोमीटर की कमी आ चुकी है। वर्तमान में वहां केवल 143 लाख वर्ग किलोमीटर बर्फ शेष बच गई है,

जो 2017 के रिकॉर्ड निचले स्तर से भी कम है। वर्ष 2000 से 2023 के बीच ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका के रेशियरों से हर साल करीब 270 अरब घन मीटर बर्फ पिघल रही है, जो वैश्विक आबादी द्वारा 30 वर्षों में उपायों किए जाने वाले पानी के बराबर है। नासा के वैज्ञानिक लिनेन बोसपवर्ट के अनुसार, अगली गरियों में और भी कम बर्फ बचने की आशंका है। इसका मुख्य कारण मानवीय गतिविधियों द्वारा तापमान में हुई वृद्धि है, विशेषकर जीवाश्म ईंधनों के अत्यधिक उपयोग से। जैसे-जैसे वैश्विक तापमान बढ़ता है, रेशियर बनने की तुलना में कई अधिक तेजी से पिघलते हैं, जिससे उनका अस्तित्व खतरे में पड़ रहा है। यह संकट केवल बर्फ के खत्म होने का नहीं, बल्कि पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व पर मंशरत खतरे का संकेत है।

सरकारी रिपोर्ट और वैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार, हिमालयी रेशियर जलवायु परिवर्तन के कारण अलग-अलग दर से तेजी से पिघल रहे हैं। यह न केवल पारंपरिक शोध संस्थान नैनीताल एवं दिल्ली विश्वविद्यालय के अध्ययन से पता चलते है कि हिमालय में वायु प्रदूषण का मुख्य कारण जीवाश्म ईंधनों का बढ़ता उपयोग है, विशेषकर वाहनों की बढ़ती संख्या के कारण। हिमालयी क्षेत्र अब गंभीरकरण और जल संरक्षा दबाव से जूझ रहा है। वहीं, ग्लोबल वार्मिंग से पिघलते रेशियरों के कारण बन रही शीतल गंभीर खतरा उत्पन्न कर रही है। इसरो के अनुसार, हिमालय की 2,432 रेशियर श्रृंखला में से 672 का आकार तेजी से बढ़ रहा है, जिनमें नार्वी की 130 श्रृंखला शामिल है। इनका तेजी से पिघल रहा है, जो वैश्विक जल संकट को और गंभीर बना रहा है।

वैज्ञानिक चेतावनी देते हैं कि यदि वैश्विक तापमान में 1.5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है तो सदी के अंत तक एक-तिहाई और यदि वह वृद्धि 2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचती है तो दो-तिहाई हिमालयी रेशियर समाप्त हो सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने चेतावनी दी कि नेपाल के पहाड़ों से एक-तिहाई बर्फ पहले ही खत्म हो चुकी है। भारत और चीन जैसे प्रमुख देशों उत्तरजनों को बंधन बसे इस क्षेत्र में नेपाल के रेशियर 65 फीसदी तक पिघल चुके हैं, और अगर यह हाल रहा तो हिंदुकुश-हिमालय क्षेत्र के 75 फीसदी रेशियर इधर सदी के अंत तक खत हो सकते हैं। रेशियरों को इस संकट से यह स्पष्ट है कि अब समय शब्दों का नहीं, कार्यों का है। जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता खत्म करना, वैश्विक तापमान वृद्धि को सीमित करना और जल स्रोतों को संरक्षित करना मानवता की सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। आर्यमंद प्रेक्षण एवं विज्ञान शोध संस्थान नैनीताल एवं दिल्ली विश्वविद्यालय के अध्ययन से पता चलते है कि हिमालय में वायु प्रदूषण का मुख्य कारण जीवाश्म ईंधनों का बढ़ता उपयोग है, विशेषकर वाहनों की बढ़ती संख्या के कारण। हिमालयी क्षेत्र अब गंभीरकरण और जल संरक्षा दबाव से जूझ रहा है। वहीं, ग्लोबल वार्मिंग से पिघलते रेशियरों के कारण बन रही शीतल गंभीर खतरा उत्पन्न कर रही है। इसरो के अनुसार, हिमालय की 2,432 रेशियर श्रृंखला में से 672 का आकार तेजी से बढ़ रहा है, जिनमें नार्वी की 130 श्रृंखला शामिल है। इनका तेजी से पिघल रहा है, जो वैश्विक जल संकट को और गंभीर बना रहा है।

हिन्दू संगठनों ने फूँका ममता बनर्जी का



संवाददाता-श्रावस्ती। हिन्दू युवा बाहिनी के कार्यकर्ताओं ने पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पुतला फूँका। साथ ही राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन अतिरिक्त मजिस्ट्रेट को सौंपा। हिंदुओं के पलायन को रोकने व ममता सरकार को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करने की मांग की।

वक्क संशोधन विल के विरोध की आड़ में पूरे पश्चिम बंगाल में हिंसा फैली हुई है। आक्रांतों की ओर से हिन्दुओं के घर, दुकानें चलाए जा रहे हैं। जिसके चलते हिन्दू समुदाय के लोग पलायन करने को मजबूर हैं। इस हिंसा को लेकर पूरे

पुतला, सौंपा ज्ञापन

प्रारम्भ हुई हिंसा अब संपूर्ण बंगाल में फैल चुकी है। उन्मादी जिहादी भीड़ ने हिंदुओं के 200 से अधिक घरों और दुकानों को लूट कर जला दिया। सैकड़ों हिंदुओं को बुरी तरह घायल किया व तीन नागरिकों की निमोन हत्या की गई। जिसके चलते 500 से अधिक हिंदू परिवारों को मुर्शिदाबाद से पलायन करना पड़ा है। यह क्रूर देश का हिन्दू बर्दाश्त नहीं करेगा।

लोगों ने मांग की कि ममता सरकार भारत का बर्खास्त किया जाए। साथ ही बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागूया जाए। हिंसा की जांच एनआइए से कराई जाए। बंगाल की मुख्य व्यवस्था का संचालन केंद्रीय सुखा बलों को सौंपा जाए। बंगालीयों व रोहिंया चुसपंडियों की पहचान कर उन्हें देश से निकाला जाय। इस मोर्चा पर विभाग मंत्री अजय जसवाल के साथ ही जिला मंत्री कृष्ण देव सिंह, सुरेश गुप्ता, सदीप कसौधन, देवेन्द्र सिंह, शिशाल शिवरात्र, अमित कुमार सिंह, वीरेंद्र शिवरामजी, रमेश गुप्ता, कमलेश सिंह, आयुष प्रताप सिंह, आशीष आर्या आदि मौजूद रहे।

सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा चला बुलडोजर



संवाददाता-गोंडा। जिले में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई। मनकापुर तहसील के बरसेनिया लखपतराय गांव में खलिहान की भूमि से अवैध कब्जा हटया गया। तृतीयलवार सत्यपाल सिंह के नेतृत्व में चलाए गए अभियान में बुलडोजर से आधा दर्जन अस्थायी निर्माण तोड़े गए। इन निर्माणों में स्नानघर और नल की बाउंड्री वाल शमिल हैं। प्रशासन ने पहले कई बार नोटिस जारी की थी। कब्जाधारियों को कई बार चेतावनी दी गई थी, लेकिन वे नहीं माने। इस कार्रवाई के बाद खलिहान की भूमि पूरी तरह से खाली हो गई है। कब्जा मुक्त हो गई है। प्रशासन ने

सभी ब्लाकों में कैप लगा कर चिन्हित किए जाएंगे

संवाददाता-श्रावस्ती। दिव्यांग लोगों को उपकरण देने के लिए सभी ब्लाकों में कैप लगा कर पंजीकरण किया जाएगा। इसके बाद जिला स्तर पर मेगा कैप लगा कर उपकरण वितरित किए जाएंगे। सोमवार से कैप का शुभारंभ किया जाएगा। जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र एवं कानपुर स्थित एल्को कंपनी के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित कैप का शुभारंभ नीति आयोग के नोडल अधिकारी धीरेन्द्र साहू सोमवार को करेंगे। पल्ला कैप सोमवार 21 अप्रैल को संयुक्त जिला अस्पताल व स्थित जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र में लगेगा। जवाकि दूसरा केंप 22 अप्रैल अखिरपुरवारी में ब्लाक स्नागार में, तीसर केंप 23 अप्रैल को सिररिया ब्लाक स्नागार में, चौथा केंप 24 अप्रैल को चम्पुनाथ ब्लाक स्नागार में, पांचवा केंप को उदोनो ब्लाक स्नागार में एवं अंतिम व छठा केंप 26 अप्रैल को गिलौला ब्लाक स्नागार में आयोजित किया जायेगा। इन कैपों में दिव्यांग जनों की आवश्यकता का चिकनीकरण करके पंजीकरण किया जाएगा। इसके बाद

भाजपा प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हुई सभासद

संवाददाता-श्रावस्ती। भिना नगर पालिका की वार्ड संख्या 9 स्थित लाइन वार्ड की रिक्त हुई सीट पर उप चुनाव में भाजपा प्रत्याशी शोभा कुमारी निषाद निर्विरोध निर्वाचित हुईं। भाजपा जिलाध्यक्ष डॉ मिश्रीलाल वर्मा व निर्वाहित प्रत्याशी ने तहसील में प्रमाण पत्र प्राप्त किया। भिना नगर पालिका भिना के वार्ड नं 9 स्थित लाइन में सभासद पद के लिए उप चुनाव कराय गया। जिससे सभा और एक निर्दलीय प्रत्याशी ने नामांकन करवा था। लेकिन जांच के दौरान सभा और निर्दलीय प्रत्याशी का नामांकन तनवीकी कर्मियों के कारण निरस्त कर दिया गया था। इसलिए भाजपा प्रत्याशी का निर्विरोध निर्वाचन तय हो गया था। शनिवार को रिटर्निंग आफीसर ने शोभा कुमारी निषाद टैंट हाउस के गोदाम में लगी

संवाददाता-महराजगंज। 6 मीन क्षेत्र में स्थित सिकख मंदिर चौराहे पर एक बड़ी अग्निकांड की घटना सामने आई जिसमें आर.के. टैट हाउस के गोदाम में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। टैट हाउस के मालिक राम कुमार विवेकमोह से अनुपस्थित में कुर्ली, मेज, गैट, गद्दा, शमियान और बर्तन जैसा कीमती सामान रखा था। गोदाम से बुझा निकलने पर स्थिति के सदस्य बाहर निकल आए। स्थानीय प्रमोणीय और आसपास के लोगों ने तुरंत आग बुझाने का प्रयास किया। फायर ब्रिगेड की टीम भी मक़द पर पहुंची और कड़ी मशक़त के बाद आग का क़बू पाया। लेकिन तब तक गोदाम में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो चुका था।

स्कूल में नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म, बंगाली शिक्षक ने वीडियो बनाकर किया ब्लैकमेल, पुलिस ने किया गिरफ्तार

संवाददाता-कुशीनगर।

कोचिंग के लिए स्कूल जल्दी पहुंची गयी तो कोचिंग के टीचर ने गुंडे अपने स्कूल में ही स्थित अपने आवास में बुलाया। मेरे साथ जोर जबरदस्ती की और विडियो बनाया। मुझे धमकाया की अगर बुलाने पर नहीं आई तो वीडियो मां बाप को तुम्हारे दिखा दूंगा। उसके बाद कई बार सर जी ने मेरे साथ संबंध बनाए। उसने कहा कि वह वह बंगाल को रहने वाला है और शादी करेगा।

यह कहना है एक निजी स्कूल में पढ़ाने वाले 7वीं कि 14 वर्षीय नाबालिग छात्रा का। जिस के साथ उसी के स्कूल के 42 वर्षीय शिक्षक ने रहे किया। पश्चिम बंगाल के रहने वाले श्याम मंडल नाम के शिक्षक ने विशुनपुरा इलाके में स्थित शाला कृष्ण इंटरमीडिएट कॉलेज में एक साल से पढ़ा रहा था। जहां कोचिंग में आई पीछिता को पहले अपने झाले में लिया। वह उसके साथ 8 महीने से उसके साथ संबंध बना रहा था। उसका वीडियो बनाया, धमकी दी अगर किसी को बताया तो वायरल कर दूंगा।

पीछिता के पिता ने बताया- आरोपी ने उनकी बेटी का मोबाइल नंबर लेकर उससे बात करना शुरू किया। बाद में उसने मां-पिता के नंबर भी ले लिए। आरोपी ने पीछिता से बताया कि उसका घर बंगाल में के साथ पिता और मां ने आरोपी को 6 र दोबाओ और पुलिस को सौंपा। पीछिता की मां ने बताया कि



आरोप लगा था, जिसके बाद उसे स्कूल से हटा दिया गया, लेकिन वह फिर भी आरोपी में रहता और मेरे घर आता-जाता रहता था। इन दिनों वह अपने गांव गया था।

पीछिता के पिता ने बताया कि आरोपी ने उनकी बेटी का मोबाइल नंबर लेकर उससे बात करना शुरू किया। आरोपी ने उनकी बेटी का मोबाइल नंबर लेकर उससे बात करना शुरू किया। मामला तब सामने आया, जब शिक्षक ने पीछिता के पिता को फोन किया। संदेह होने पर पिता ने फोन से पृच्छाकृत, तब बेटी ने उसे हुए पूरी घटना बताया। जब उसकी करतूत जान गया तो बेटी ने कहलवाया की वो घर से भाग निकली है लेने आया। 16 अप्रैल को टीचर उसे लेने के लिए वह बिहार बाईर आया। जहां से बंगाल ले जाकर बेटी को बेचने के की तैयारी में था। लेकिन बेटी के साथ पिता और मां ने आरोपी को 6 र दोबाओ और पुलिस को सौंपा। पीछिता की मां ने बताया कि

मेरी बेटी के साथ बंगाल के रहने वाले 42 वर्षीय मास्टर ने ही रहे किया। छोटी बेटी पर भी दुरी नजर रहता था, छेड़छाड़ भी किया। जब मुझे पता चला तो मैं उसे पकड़वाकर पुलिस को दिया। लेकिन स्कूल के प्रिंसिपल ने पैसे पुलिस से दो दिए हैं, जिसके वजह से पुलिस ने आरोपी शिक्षक को थाने में बैठाए रखी है जेल नहीं भेज रही। तीन दिन से उल्टे मुझे धमकी दी जा रही। बड़े विश्वास से बच्चों को स्कूल भेजते हैं, लेकिन वहां ही ऐसा किया गया। जब थाने पर गया तो आरोपी नहीं मिला तो अब पुलिस अधीशक से त्वाय की गुहार कर लिया गया है।

सशस्त्र सीमा बल भिनगा में सैनिक सम्मेलन का आयोजन

संवाददाता-श्रावस्ती।

एसएफबी कमांडेंट अरुणेंद्र कुमार वरुण के नेतृत्व में बाहिनी मुख्यालय में सैनिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में भारत-नेपाल सीमा की सुरक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ करने का निश्चि दिया। कमांडेंट ने जवानों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने के लिए शारीरिक गतिविधियों और खेलकूद को अपनी दिनचर्या में शामिल करने पर विशेष जोर दिया।

इसके साथ ही मोटे अनाज के उपयोग की अपील की। वहीं अत्याचार के लिए प्रोत्साहित किया गया। सम्मेलन के दौरान जवानों की समस्याओं को सुना और समाधान का आश्वासन दिया। कमांडेंट ने सभी जवानों को कर्तव्य परायणता और अनुशासन बनाए रखने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान उप कमांडेंट निरुपेश कुमार, पीयूष सिन्हा सहित अन्य अधिकारी व जवान मौजूद रहे।

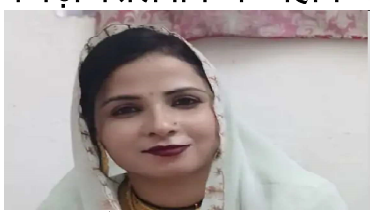
मुर्शिदाबाद हिंसा पर विश्व हिंदू परिषद ने राष्ट्रपति को सौंपा ज्ञापन

संवाददाता-कुशीनगर।

पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्क कानून को लेकर हुई हिंसा का मामला सामने आया है। विश्व हिंदू परिषद ने इस संबंध में राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा है। मुर्शिदाबाद में 11 अप्रैल को हुई हिंसा में हिंदुओं के 200 से अधिक घर और दुकानें जला दी गईं। इस हिंसा में तीन लोगों की मौत हो गई। कई महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार की घटनाएं भी सामने आईं। हिंसा के बाद 500 से अधिक हिंदू परिवारों को मुर्शिदाबाद छोड़ना पड़ा। विश्व हिंदू परिषद के पारदर्शन कुशीनगर जिलाध्यक्ष मुकेश त्रिपाठी ने ज्ञापन में कहा कि यह हिंसा पूरे बंगाल में फैल रही है। स्थानीय प्रशासन दगाइयों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहा है। कुछ जगहों पर

प्रशासन दगाइयों का समर्थन कर रहा है। ज्ञापन में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर आरोप लगाया गया है। उन्होंने पीछित परिवारों की मदद करने की बजाय दंगा भड़काने वाले इमरानों से मुरातकता की है। विश्व हिंदू परिषद ने केंद्र सरकार से बंगाल का प्रशासन अपने हाथ में लेने की मांग की है। ज्ञापन में कई संघ मांगों की की गई हैं। इनमें बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने, हिंसा की छाप जांच कराने और संस्था सुखा बलों को कानून व्यवस्था का जिम्मा देने की मांग शामिल है। साथ ही बांग्लादेशी और रोहिंया चुसपंडियों की पहचान कर उन्हें निष्कासित करने और बांग्लादेश सीमा पर तार लगाने की मांग की गई है।

दर्जी पति के कस्टमर के साथ पत्नी फरार, कपड़ा सिलवाने के बहाने आता था युवक



संवाददाता-गोंडा। एक चौकाने वाला मामला सामने आया है। यहां चार बच्चों की मां अपने दर्जी पति के ग्राहक के साथ फरार हो गईं। महिला अपनी तीन वर्षीय मामूस बेटी को भी साथ ले गई है। मामला नगर कोतवाली क्षेत्र का है, जहां पीछित पति ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। पीछित रईस अहमद का आरोप है कि उसकी पत्नी नूरजहां को इकबाल काजमी नामक युवक बहला-फूसलाने अपने साथ ले गया है। इकबाल पहले उसके घर सिलाई के बहाने आता-जाता था, लेकिन अब पत्नी और बेटी दोनों लापता हैं।

पति ने बताया कि दो दिन पहले पत्नी हंसी-खुशी घर से निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। रईस अहमद ने बताया कि रमजान के महीने में इकबाल उनके घर पर ही रहता था और सिलाई के काम में मदद करता था। इसी दौरान उसकी पत्नी से नजदीकियां बढ़ी। जब रईस को शक हुआ तो उसने पांच दिन पहले इकबाल को घर आने से मना कर दिया था। इसके बाद 17 तारीख की शाम 6 बजे से ही पत्नी और बेटी लापता हैं। रईस ने बताया कि इकबाल की उम्र करीब 53 साल है और वह पहले से शादीशुदा है। उसकी पत्नी

सपा का विरोध प्रदर्शन: कानून व्यवस्था और दलित उत्पीड़न के मुद्दे पर डीएम को सौंपा ज्ञापन



की मौत दो महीने पहले हुई है और उसके भी बच्चे हैं। दूसरी ओर, नूरजहां की उम्र 30 साल है। रईस ने पुलिस से अपील की है कि उसकी पत्नी और बेटी को जल्द से जल्द बरामद किया जाए और इकबाल काजमी पर सख्त कार्रवाई हो। नगर कोतवाल विवेक कुमार त्रिवेदी ने बताया कि गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। नामांकी रिपोर्ट में किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, फिर भी पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। महिला और बच्ची की तलाश जारी है। पत्नी और बेटी के जाने से रईस अहमद पूरी तरह टूट चुका है। घर पर तीन छोटे-छोटे बच्चों का खे-रो कर बुरा हाल है। रईस ने मीडिया से बातचीत में कहा, 'हमारी बस यही फरियाद है कि हमारी बीवी और बच्ची हमें वापस मिल जाना और जिसने यह सब किया है, उसे सजा मिले। इस घटना ने पूरे मोहल्ले में सनसनी फैला दी है और लोग तरह-तरह की चर्चाएं कर रहे हैं। पुलिस की जांच में अब यह देखना होगा कि महिला अपनी मन में क्या कि प्रेक्ष में कानून

पिकअप से 6 गोवंश बरामद ,तीन को तस्कर गिरफ्तार

संवाददाता-देवरिया। नटपार रानी पुलिस ने शनिवार को एक बड़ी कार्रवाई में नौ तस्करों का भंडाबान किया। पुलिस ने फुलवरिया चौकाल से चतुकी रोड पर करमा बाबा से एक पिकअप वाहन से 6 गोवंशीय पशुओं को बरामद किया। गोवंशी अश्लील वित्ताक और निंदश पर चल रहे अभियान के दौरान मुखविव से सांध्य वाहन की सूचना

मिली। पुलिस को देखकर पिकअप (नं 50 उउ 3423) चालक भागने लगा। मामले के दौरान वाहन सड़क किनारे बसे से टकरा गया। इस दौरान तीन आरोपी भागने लगे, लेकिन सवार से एक पिकअप वाहन से 6 गोवंशीय पशुओं को बरामद किया। गोवंशी अश्लील वित्ताक और निंदश पर चल रहे अभियान के दौरान मुखविव से सांध्य वाहन की सूचना

पशुओं को बिहार ले जा रहे थे। थानाध्यक्ष नता प्रसाद के अनुसार, आरोपियों के खिलाफ गोपाल निवारण अभिनियम और पशु क्रूरता निवारण अभिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। पिकअप वाहन को जब्त कर लिया गया है। सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है।

संपूर्ण समाधान देवस का आयोजन, डीएम-एसपी ने सुनी समस्याएं

संवाददाता-बलरामपुर। शनिवार को तहसील स्तर में संपूर्ण समाधान देवस का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी प्रमन अग्रवाल और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम को मौके पर जांच का दिशेदिश दिया गया। डीएम ने चेतावनी दी कि शिकायतों के समा। जा में लापरवाही या नलत रिपोर्निंग पर कड़ी कार्रवाई होगी। कार्यक्रम में संपूर्ण समाधान देवस के अधिकारियों को शिकायतों का समग्रवद और गुणवत्तापूर्ण समाधान करने का निदेश दिया। उन्होंने कहा कि मौके पर निपटारा जा समने वाले मामलों को तुरंत सुलझाया जाए। भूमि विवाद

राष्ट्रीय एकता का

संवाददाता-गोंडा। शहर के शुभचिंतक पीजी कॉलेज में शनिवार को हिन्दी विभाग एवं आंतरिक गुप्तता आचार्यल प्रकोष्ठ (आईएनएसटी) के संयुक्त तत्वाधान में सर्वप्रथम कुटुम्बक का महाविद्यालय राष्ट्रीय एकता का प्रतिष्ठित विषय पर एक विदेशीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। जिसकी अध्यक्षता मा पारेस्वरि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. रवि शंकर सिंह ने की। मुख्य अतिथि लखनऊ विश्वविद्यालय के हिन्दी एवं पश्चिमप्रति विभाग के पूर्व अध्यक्ष एवं प्रिंसिपल साहित्यकार प्रो. सूर्य प्रसाद दीक्षित और विशिष्ट अतिथि लखनऊ विश्वविद्यालय के हिन्दी विभागाध्यक्ष

प्रतिष्ठिब पर संगोष्ठी का आयोजन हुआ

प्रो. पवन अग्रवाल रहे। कार्यक्रम की शुभचिंतक पीजी प्रमन, सर्वप्रथम वंदना और स्वागत गीत सुनवाई। प्रमोद प्रो. रविशंकर गुप्ता वसे ने संगोष्ठी की प्रवृत्ति एवं उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए मईकम 2025 के दिव्यांग प्रमन का बौद्धिक विकासन बताया। प्रो. सूर्य प्रसाद दीक्षित ने कुंम की सांस्कृतिक परंपरा, धार्मिक आधार और वैश्विक मल्ल पर विस्तृत व्याख्यान दिया। प्रो. रविशंकर सिंह ने कहा कि भारतीय संस्कृति पुनर्जीव और महाकुंम उत्कर्षी जिला अभिनिष्ठ। उन्होंने बताया कि इस बार 74 देशों के प्रतिनिधियों के साथ नगर में भाग लेने भारत की सांस्कृतिक शांति को विवध मंच पर

प्रतिष्ठिब पर संगोष्ठी का आयोजन हुआ

प्रो. पवन अग्रवाल रहे। कार्यक्रम की शुभचिंतक पीजी प्रमन, सर्वप्रथम वंदना और स्वागत गीत सुनवाई। प्रमोद प्रो. रविशंकर गुप्ता वसे ने संगोष्ठी की प्रवृत्ति एवं उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए मईकम 2025 के दिव्यांग प्रमन का बौद्धिक विकासन बताया। प्रो. सूर्य प्रसाद दीक्षित ने कुंम की सांस्कृतिक परंपरा, धार्मिक आधार और वैश्विक मल्ल पर विस्तृत व्याख्यान दिया। प्रो. रविशंकर सिंह ने कहा कि भारतीय संस्कृति पुनर्जीव और महाकुंम उत्कर्षी जिला अभिनिष्ठ। उन्होंने बताया कि इस बार 74 देशों के प्रतिनिधियों के साथ नगर में भाग लेने भारत की सांस्कृतिक शांति को विवध मंच पर

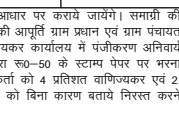
लोगों को जागरूक करने के लिए चलाए अभियान

संवाददाता-गोंडा। लोक अदालत के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाकर ग्रामों को लोक अदालत का लाभ दिलया जाए। जिससे इसका उद्देश्य पूरा हो सके। ये निदेश राष्ट्रीय लोक अदालत की नंडल अधिकारी अरुण जिला जज नमता अग्रवाल एवं जिला अधिकारी सीमा प्रबिचकर के संधि अग्र अरुण जिला जज दानिश हसन ने सिविल जॉंट के वीडियो कॉन्फरेंस वक्म में आयोजित हो बताया कि 10 मई को साल की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होना है।

शाली समारोह में सफाई करने गए कार्यधारियों से मापीट संवाददाता-महराजगंज।

सुभाष नगर वार्ड में एक शाली समारोह के दौरान सफाई कर्मियों के साथ मापीट का मामला सामने आया है। नगर पालिका के दो सफाई कर्मी शाली समारोह स्थल पर सफाई कार्य के लिए तैनात किए गए थे। शनिवार को दोहरा में जब सफाई कर्मी अपना काम कर रहे थे, तब शाली वाले घर के लोगों ने उनके साथ गाली-गलौज शुरू कर दी। सफाई कर्मियों द्वारा विवध करने पर उनके साथ मापीट हो गया। इस घटना से आओचित सफाई कर्मियों ने शिकायत दर्ज किया। उन्होंने जलूस निकाला और नाबंजी की। प्रदर्शनकारियों ने कुछ समय के लिए गिरफ्तार सभी छ-730 को जाम कर दिया। स्थानीय लोगों की समझावश के बाद सफाई कर्मियों ने नगर चौकी में शिकायत दर्ज कराई। जिला प्रमारी धीरज जायसवाल ने बताया कि शाली प्राप्त हो गई है और मामले में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

बारिश ने किसानों के अरमानों पर फेरा पानी



अदालत में हाजिर होकर मुकदमा मजकूर जबाबदेही कीजिये और अगर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा वगैर हाजिरी आपके मसमूअ और फैसला होगा।

बवक्त मेरे दस्तखत और

वगैर हाजिरी आपके मसमूअ और
फैसला होगा।
बवक्त मेरे दस्तखत और

गोरखपुर कार्यालय—
इलाहीबाग गोरखपुर।
मो09450567450 9336715406,

(सुधा देवी) ग्राम प्रधान	(अवधेश कुमार) ग्रामपंच / ग्रामिकाग्रि	04 सन 2025 ई0 जारी किया गया।	04 सन 2025 ई0 जारी किया गया।	04 सन 2025 ई0 जारी किया गया।	04 सन 2025 ई0 जारी किया गया।	04 सन 2025 ई0 जारी किया गया।	04 सन 2025 ई0 जारी किया गया।
पत्रांक मेमो / 18.04.2025	वित्तीय वर्ष 2025-26	द0 हाकिम	द0 हाकिम	द0 हाकिम	द0 हाकिम	द0 हाकिम	द0 हाकिम